REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

# कृषि एवं ग्रामीण विकास और पंचवर्षीय योजनाएं

डॉ. विजय कुमार सिंह[1], हरीश कुमार[2]
[1]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल.
[2]एम.ए.,नेट (शोधरत)

कृषि भारतीय जीवन, सभ्यता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत है जिसका विस्तार ग्रामीण जीवन में ही परिलक्षित होता है। गॉव के अधिकांश लोग कृषि से सम्बन्ध रखते हैं जो अपनी पिछड़ी अवस्था में है। ग्रामीण आर्थिक विकास से ही देश का सर्वांगीण (सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक) विकास सम्भव है। गॉव की आर्थिक स्थिति सुधारने का सीधा सा अर्थ है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लेकिन दुर्भाग्यवश कृषि क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। आज भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद, उन्नतशील बीज, सिंचाई की सुविधा तथा कृषि से सम्बन्धित यंत्र समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत को गरीबी, बेरोजगारी, कृषि की निम्न उत्पादकता और निम्न औद्योगिक विकास जैसी समस्याएं विरासत में मिली थीं। तत्कालीन भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिकांश क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था, इसलिए उस समय भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आवश्यकता तीव्रता के साथ महसूस की गयी। विश्व के कुल भूभाग का २.४ प्रतिशत भाग भारत के पास है जबकि विश्व की १७.५ प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए तथा देश की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि और उद्योगों पर निर्भरता बढ़ी है। रूस के वैज्ञानिक समाजवाद की सफलता से प्रभावित होकर भारत ने वैज्ञानिक समाजवाद और पूँजीवाद के बीच का रास्ता चुना तथा भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को अवसर दिया गया। इसके अन्तर्गत लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना था। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गयी।

## विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति

### प्रथम पंचवर्षीय योजना

इस योजना में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा और खाद्य संकट को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनाज, दाल, फल, सब्जी, दूध आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना था। परिणामस्वरूप कृषि के अन्य क्षेत्रकों का काफी विकास हुआ, जिस पर ग्रामीण समाज की निर्भरता और अधिक बढ़ गयी। अपनी खाद्यान्न आवश्यकता के लिए दूसरे देशों से संधि राष्ट्र के स्वाभिमान के विपरीत होती क्योंकि अधिक खाद्यान्न उत्पादकता वाले देश अतिरेक अनाज उत्पादन से दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। उस समय इस बात को महसूस किया गया कि देश की

प्रगति तभी सम्भव है जब दूसरे देशों पर खाद्यान्न निर्भरता समाप्त हो और हम इस दिशा में आत्मनिर्भर हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य ६१ लाख टन रखा गया था जबकि वार्षिक औसत उत्पादन ६७ लाख टन हुआ। इस तरह पहली पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य में सफल रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को कुल राजस्व आवंटन का ३१ प्रतिशत भाग प्रदान किया गया। इस योजना राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय में ११ प्रतिशत और खाद्यान्न उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई इसके अतिरिक्त १६ मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ—साथ ४५ लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार भी मिला।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना

इस पंचवर्षीय योजना काल में कृषि की अपेक्षा उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इस योजना के रणनीतिकारों का मानना था कि कृषि का विकास अब स्वयं होता रहेगा और बड़े उद्योगों के विकास से विदेशों पर निर्भरता कम होगी। इस योजना काल में कुल व्यय का २० प्रतिशत भाग आवंटित किया गया। परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी आयी २१० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं लेकिन प्रति व्यक्ति आय घटकर ८ प्रतिशत हो गयी।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

इस बात का अनुभव किया गया कि विगत दो योजनाओं में कृषि की विकास दर देश के आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई है, इसलिए कृषि का विकास खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और कृषि के समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में गहन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि जिला कार्यक्रम और अधिक उपज वाली किस्मों पर विशेष ध्यान दिया गया। मानसून असफलता, सूखा और अकाल जैसी बाधाओं के बावजूद कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हासिल की गयी।

## चौथी पंचवर्षीय योजना

कृषि क्षेत्र में विकास के लिए अनुसंधान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष बल देते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गयी थी और इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि देश नवीन तकनीकी के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। पशुधन कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम इस परियोजना में उठाया गया जिसके जनक वर्गीज कुरियन थे अर्थात् १९७० में श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) की शुरुआत हुई और देश की दूध के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ी। कुल योजना व्यय का २२ प्रतिशत भाग इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए आवंटित किया गया था, साथ ही साथ उत्पादन को आगामी १० वर्षों में ५ प्रतिशत तक बढ़ाकर ग्रामीण जनसंख्या को अधिक से अधिक विकास कार्यों में लगा कर उन्हें सीधे लाभ पहुँचाते हुए सामाजिक न्याय दिलाने की बात की गयी।

## पाँचवी पंचवर्षीय योजना

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें और आवास की व्यवस्था आदि को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। इस परियोजना में कुल परिव्यय का १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया था। खाद्यान्न उत्पादन में जिस आत्मनिर्भरता की बात की गई थी और उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं अधिक उत्पादन हुआ। इसे द्वितीय हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है।

## छठवीं पंचवर्षीय योजना

छठवीं योजना में भूमि सुधार कार्यक्रमों को तीव्र गति से लागू करना, अधिकाधिक रोजगार का सृजन करना, निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, नवीन तकनीकी का लाभ अधिकांश किसानों तक पहुँचाना तथा कृषि विज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार में वृद्धि का साधन बनाना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। साथ ही इस योजना से ही हरित क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत हुई

और कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश एवं प्रबंधन पर बल दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम १९८०, नाबार्ड बैंक की स्थापना १९८२, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम १९८३, डेयरी विकास कार्यक्रम TRYSEM और राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम की शुरुआत भी इस पंचवर्षीय योजना में हुई जिसका सीधा फायदा ग्रामीणों को पहुँचा।

## सातवीं पंचवर्षीय योजना

इस योजना में गरीबी कम करने, रोजगार के अवसर में वृद्धि तथा उत्पादन को बढ़ाने की प्राथमिकता पर जोर दिया गया, साथ ही कृषि विकास की गति में तीव्रता लाते हुए कृषि के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों को ग्रामीण इलाकों के निर्धनता निवारण कार्यक्रमों से जोड़ना सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त अविकसित या कम विकसित क्षेत्रों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हुए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और चकबंदी योजना पर बल दिया गया। इस योजना में कपास को छोड़कर सभी फसलों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा।

## आठवीं पंचवर्षीय योजना

इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और उससे प्राप्त लाभ को स्थाई एवं सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ इस बात का भी प्रयास किया गया कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके और कृषि प्रतिस्पर्धी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसके वाणिज्यिक स्वरूप का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इस योजना में सिंचाई सुविधाओं को २७ लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की बात की गयी, साथ ही भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए निर्यात के लिए रणनीति बनाना भी इस योजना में शामिल था। इस योजना में कृषि की विकास दर ४.७ प्रतिशत रही।

## नौवीं पंचवर्षीय योजना

इस योजना में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ उसके विभिन्न आयामों जैसे भूमि सुधार, नई कृषि तकनीक, कृषि साख और विनियोग विपणन एवं कृषि उत्पाद मूल्य पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस सन्दर्भ में यह योजना असफल रही क्योंकि इस दौरान कृषि विकास की दर २.५ प्रतिशत रही।

## दसवीं पंचवर्षीय योजना

दसवीं योजना में कृषि विकास पर बल दिया गया। इसके अन्तर्गत निर्धनता अनुपात में कमी, साक्षरता प्रतिशत, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में राष्ट्रीय कृषि नीति (National Agriculture Policy) को अपनाया गया जिसके अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र की विकास की दर इस योजना काल में २.४ प्रतिशत रही।

## ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को विकसित करने को सर्वोच्च वरीयता दी गयी। कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, नवीन रोजगार के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को कम करने तथा भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करना इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे। कृषि की विकास दर का लक्ष्य ४ प्रतिशत रखा गया लेकिन इसे प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल पायी। इसमें निर्धनता अनुपात १० प्रतिशत बिंदु कम करना, रोजगार के सात करोड़ नए अवसर पैदा करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति,

ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था।

## बारहवीं पंचवर्षीय योजना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के साथ–साथ समावेशी विकास की बात की गयी। निर्धनता अनुपात में कमी, रोजगार का सृजन, निर्मल ग्राम पंचायत, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों की स्थापना, ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों को नई तकनीक के माध्यम से आपस में जोड़ने की नीति निर्धारित करते हुए उसका क्रियान्वयन करना इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये थे।

## सुझाव:–

- कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, साथ ही सरकारी नीतियों को लचीला और व्यावहारिक बनाते हुए एक ऐसे माहौल का निर्माण करना जिससे कृषि और उद्यमियों की रचनात्मकता को बढ़ावा और समर्थन मिल सके।
- कृषिगत क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का विस्तार करने की आवश्यकता है जिससे सिंचाई के अभाव में बेकार पड़ी भूमि पर भी कृषि की जा सके और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग एवं आपूर्ति के मध्य संतुलन की स्थिति बनायी जा सके।
- कृषि में नवीन तकनीकी और नवाचारों के उपयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण की सहायता से कृषि उत्पादों के उत्पादन को आशातीत स्तर तक बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए उन्नतशील बीज, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा, जैविक खाद खरपतवार नाशक, तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ इस पर सब्सिडी भी दी जानी चाहिए।
- कृषिगत उपजों के अधिकतम समर्थन मूल्य के साथ–साथ किसानों को बाजार और बाजार सम्बन्धी जानकारी मिलनी चाहिए तथा सामयिक बाजार के अभाव में कृषि उत्पादों के भण्डारण की व्यवस्था भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उपजों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए तथा साहूकारों और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना चाहिए।

अत: यह कहा जा सकता है कि कृषि की उपेक्षा दीर्घकालीन कुपोषण, भुखमरी और गरीबी को जन्म देती है और यह सभी धर्म और तर्क से ऊपर हैं, जिनसे सामाजिक असमानता को बल मिलता है तथा ग्रामीण विकास अवरुद्ध होता है। जबकि कृषि के प्रति अनुकूल व्यवहार और नीतियां पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी जैसे रोजगार परक विकास को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण विकास में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इसलिए कृषि को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने की आवश्यकता है।